

Participants : [Maheshwari Smt. Kiran](#)

>

Title : Problems being faced by mustard growers in Rajasthan.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि राजस्थान में जो सरसों उत्पादक हैं, उनके साथ केन्द्रीय कृषि मंत्रालय अन्याय कर रहा है। यह इस बात से साफ जाहिर होता है कि जहां राजस्थान में 40 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, वहीं सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 1715 रुपये रखा है। नैफेड यह सरसों राजस्थान से राजफैड के द्वारा खरीदता है। इस तरह का समर्थन मूल्य रखने के बाद जो 40 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ प्रतिशत लेना तय किया है। अभी करीब 33 प्रतिशत सरसों की ही खरीद की जा रही है। इस प्रकार कुल 12 लाख टन सरसों की खरीद की गई है। वहां उत्पादित शेष बची हुई सरसों के भंडारण की जगह नहीं मिल रही है। इस कारण से वहां के किसान बहुत बुरी हालत में हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सरसों को विशेष उत्पादन की श्रेणी में लाया जाए, ताकि राजस्थान के किसानों को डब्ल्यू.टी.ओ. और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश से छुटकारा मिल सके। मैं समझती हूँ कि यदि सरसों को विशेष श्रेणी में लिया जायेगा तभी राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को थोड़ी राहत महसूस होगी।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरसों का तेल है तथा जो अन्य उत्पादन हो रहा है, वे सभी तेल तथा घानियों के तेल आसानी से बिकते थे। लेकिन आज मार्केट में वे तेल इम्पोर्ट हो रहे हैं और हमारे यहां विदेशी तेल आ रहे हैं। जिसके कारण आज भारतीय बाजार में करीब 56 प्रतिशत विदेशी तेल छाये हुए हैं और कम्पिटिशन में हमारे यहां के तेल नहीं बिक पा रहे हैं, जिसके कारण सारी घानियां बंद हो गई हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से या तो विदेशी तेल का इम्पोर्ट बंद करना चाहिए या इनके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे यहां के तेल को अच्छा मार्केट मिल सके। धन्यवाद।